



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1938 (श0)

(सं0 पटना 431) पटना, मंगलवार, 31 मई 2016

गृह विभाग
(कारा)

अधिसूचना
26 मई 2016

सं0 बंदी/अ०मु०-01-05/2014-3194—कारा अधिनियम, 1894 (अधिनियम 9, 1894) की धारा-59 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा-432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा हस्तक, 2012 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, :-

- नियम 476 का संशोधन:- बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 476 में प्रयुक्त वाक्यांश "कारा अधीक्षक के टिप्पण" एवं "पुलिस अधीक्षक और परिवीक्षा पदाधिकारी की अनुशंसाओं" के मध्य निम्न वाक्यांश अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) का मंतव्य,"
- नियम 479 का संशोधन:- बिहार कारा हस्तक, 2012 का नियम 479 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
" 479. पर्षद द्वारा एक या अधिक बार बंदी की समय पूर्व मुक्ति के मामले की अस्वीकृति इस पर पुनर्विचार करने में बाधा नहीं होगी। फिर भी एक बार अस्वीकृत किसी सजायापता के मामले पर पुनर्विचार एक वर्ष या पर्षद द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् ही, किन्तु इसके अंतिम विचारण की तिथि से तीन वर्षों के भीतर किया जाएगा। ऐसे पुनर्विचार के लिए पुलिस अधीक्षक का नया प्रतिवेदन आवश्यक होगा। तथापि, यदि मामला तीन वर्षों के बाद पुनर्विचार के लिए लिया जाता है तो जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा परिवीक्षा पदाधिकारी से नया प्रतिवेदन एवं न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) का नया मंतव्य प्राप्त किया जाएगा।"
- नियम 480 का संशोधन-बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 480 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
"परन्तु जब दण्डादेश किसी ऐसे अपराध के लिए दिया गया हो -
(क) जिसका अन्वेषण किसी केन्द्रीय जाँच एजेंसी जैसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा किया गया हो; अथवा
(ख) जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्ग्रस्त हो; अथवा

- (ग) जो केन्द्रीय सरकार की सेवा के किसी व्यक्ति के द्वारा तब किया गया हो, जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित था; अथवा
- (घ) जिनमें कुछ ऐसे विषय भी संबंधित हों जिनपर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, तो उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में वर्णित मामलों के संबंध में दण्डादेश का परिहार के लिए आदेश, संघ सरकार की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् दी जाएगी।
- (ड.) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) के मामलों में पर्षद का सदस्य-सचिव, सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा के पश्चात्, मामले से संबंधित अभिलेख केन्द्र सरकार को सहमति हेतु भेजेगा।
4. नियम 481 का संशोधन— (1) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 के उप-नियम (i) में, प्रयुक्त वाक्य “मृत्यु दंड प्राप्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-433क के अधीन आच्छादित निम्नांकित कोटियों के सिद्धदोष परिहार सहित 20 वर्षों तक कारावास में रहने के बाद ही समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार होंगे” निम्नलिखित वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“मृत्यु दंड प्राप्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-433क के अधीन निम्नांकित कोटियों के सिद्धदोष परिहार सहित 20 वर्षों तक कारावास में रहने के बाद भी समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे:—”
- (2) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 का उप-नियम (i) (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(क) वैसे बंदी जो बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसी हत्या जिसमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कोई अपराध सम्मिलित हो, दहेज के लिए हत्या, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे की हत्या, अनेक हत्या, अभियोजन के पश्चात कारागार में रहते हुए की गई हत्या, पैरोल पर रहने के दरम्यान की गई हत्या, आतंकवादी घटना में हत्या, तस्करी करने में हत्या या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में हत्या हेतु आजीवन कारावास में हों।”
- (3) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 का उप-नियम (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप-नियम (iv) एवं (v) जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—
“(iv) वैसे मामलों में, जिनमें आजीवन कारावास की सजा में यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि बिना परिहार या लघुकरण (Commutation) के सजायापता आजीवन कारावास का दण्ड अपने जीवनकाल के अंत होने तक भुगतेंगे, सजायापता को परिहार या लघुकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा।”
“(v) वैसे मामलों में जिनमें आजीवन कारावास की सजा में यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि एक निर्धारित अवधि जैसे 20 वर्ष 25 वर्ष या अन्य कोई अवधि पूरा किये बिना परिहार या लघुकरण का लाभ देकर सजायापता को रिहा नहीं किया जाएगा, में सजायापता को परिहार या लघुकरण का लाभ तबतक नहीं दिया जाएगा, जबतक वह दण्डादेश की निर्धारित अवधि तक का कारावास पूरा नहीं कर लेता है।
5. नियम 482 का संशोधन:— (1) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 482 का उप-नियम (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(i) आजीवन कारावास गुजार रहे बंदी से अथवा उसकी ओर से समय पूर्व मुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित कारा अधीक्षक राज्य सरकार द्वारा अधिकथित मानदण्डों के अनुसार बंदी के समय पूर्व मुक्ति हेतु कार्रवाई करेगा किन्तु आजीवन कारावास गुजार रहे बंदी के समय पूर्व मुक्ति हेतु विचारण के योग्य होने की तिथि से चार माह पूर्व से पहले प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।”
- (2) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 482 के उप-नियम (v) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (vi) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
“(vi) अधीक्षक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) से इस बारे में मंतव्य प्राप्त करेगा कि परिहार आवेदन को मंजूर किया जाए या नामंजूर किया जाए।”
- (3) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 482 के पूर्व के उप-नियम (vi) को उप-नियम (vii) के रूप में पुनर्संख्यांकित करते हुए निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—
“(vii) पुलिस अधीक्षक तथा परिवीक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा एवं न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) का मंतव्य प्राप्त हो जाने पर, अधीक्षक मामले को महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ को प्रस्तुत करेगा। महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बंदी की समयपूर्व मुक्ति या अन्यथा से संबंधित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) का मंतव्य, कारा अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा परिवीक्षा पदाधिकारी के

प्रतिवेदन/अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, मामले की जाँच करेगा। ऐसा करते समय वह राज्य दंडादेश परिहार पर्षद हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकथित सामान्य एवं विशेष मार्गदर्शनों को ध्यान में रखेगा/रखेगी। बन्दीयों को समयपूर्व रिहा करने के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न मार्गदर्शनों तथा स्थापित मानदण्डों पर भी समुचित ध्यान दिया जाएगा।”

- (4.) उप-नियम (viii) का जोड़ा जाना:—बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 482 के उप-नियम (vii) के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम (viii) जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

“(viii) जहाँ किसी केन्द्रीय विधि (Central Law) या केन्द्रीय विधि के अधीन अथवा किसी अन्य समान अपराध के अधीन आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो वहाँ राज्य सरकार को परिहार देने की एवं सजा को कम करने (commutation)की शक्ति नहीं होगी।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

राजीव वर्मा,

संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्रशासन)।

The 26th May 2016

No. Bandi/A.Mu-01-05/2014-3194—In exercise of the powers conferred under section 59 of the Prisons Act, 1894 (Act 9, 1894) and section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Governor of Bihar is pleased to make following amendments in Bihar Prison Manual, 2012 with effect from the date of issue of notification:-

1. Amendment of Rule 476:- In Rule 476 of Bihar Prison Manual, 2012 the following words and ,(come) shall be inserted between the words “the note of Prison Superintendent” and “recommendations of Police Superintendent and Probation Officer ” namely:-
“opinion of Presiding Judge of the Court (before or by which the conviction was had or confirmed),”
2. Amendment of Rule 479:- Rule 479 of the Bihar Prison Manual, 2012 shall be substituted by the following, namely:-
“479. Rejection of the case of prisoner for premature release on one or more occasions by the Board shall not be a bar for its reconsideration. However, the reconsideration of the case of a convict, rejected once, shall be under taken only after a period of one year or as specified by the Board, but within three years from the date of it’s last consideration. Fresh report from the Superintendent shall be necessary for such reconsideration. However, fresh reports from the District magistrate, Superintendent of Police and Probation Officer and opinion of Presiding Judge of the Court (before or by which the conviction was had or confirmed) may be obtained, if the matter is taken up for reconsideration after 3 years.”
3. Amendment of Rule 480:- After Rule 480 of the Bihar Prison Manual, 2012 the following proviso shall be added, namely:-
“Provided that where the sentence is awarded for the offence-
 - (a). which is investigated by Central Investigating Agency like Central Bureau of Investigation; or
 - (b). which involves the misappropriation or destruction of, or damage to, any property belonging to the Central Government; or
 - (c). which was committed by a person in the service of the Central Government while acting or purporting to act in the discharge of his official duty; or
 - (d). which involves such matters to which executive power of the Union extends,
in such cases mentioned in aforesaid clause (a) to (d) order for remission of sentence shall be given after receiving concurrence of the Union Government.

- (e). After approval of Competent Authority in cases mentioned in aforesaid clauses (a) to (d) the Member-Secretary of Board shall send the relevant records relating to the cases to Central Government for concurrence.”
4. Amendment of Rule 481:- (1) The sentence “The following categories of convicted prisoners covered under section 433A Crpc. undergoing life sentence would be entitled to be considered for premature release only after undergoing imprisonment for 20 years including remissions:” used in sub-rule (i) of Rule 481, shall be substituted by, namely-
 “The following categories of convicted prisoner covered under section 433A Cr.P.C. undergoing life sentence would not be entitled to be considered for premature release even after undergoing imprisonment for 20 years including remission:”
- (2) Sub-rule (i) (a) of Rule 481 of Bihar Prison Manual, 2012 shall be substituted by the following, namely-
 “(a) Such convicts who have been imprisoned for life for rape, rape with murder, dacoity with murder, murder involving offence under the Protection of Civil Rights Act, 1955, murder for dowry, murder of a child below 14 years of age, multiple murder, murder committed after conviction while inside the prison, murder during parole, murder in terrorist incident, murder in smuggling operation, or murder of a public servant on duty.”
- (3) After sub-rule (iii) of Rule 481 of Bihar Prison Manual, 2012 following new sub-rule (iv) and (v) shall be added, namely-
 “(iv) In such cases in which life sentence has been awarded by specifying that the convict shall undergo life sentence till the end of his life without remission or commutation, benefit of remission or commutation shall not be given to convict.”
 “(v) In such cases in which life sentence has been awarded by specifying that the convict shall not be released by granting remission or commutation till he completes a fixed term of 20 years or 25 years or like, remission or commutation shall not be granted to a convict until he completes the fixed term as prescribed in the sentence.”
5. Amendments of Rule 482:- (1) Sub-rule (i) of Rule 482 of the Bihar Prison Manual, 2012, shall be substituted by the following, namely-
 (1) “After receiving application for remission from or on behalf of life convict, the concerned Superintendent of Prison shall initiate the case for premature release as per the criterion laid down by the State Government in that behalf but application received prior to four months from the date when the prisoner would become eligible for consideration of premature release shall not be considered”.
- (2) After sub-rule (v) of rule 482 of the Bihar Prison Manual, 2012 the following new sub-rule (vi) shall be added, namely-
 “(vi) The Superintendent shall obtain opinion of the Presiding Judge of the Court (before or by which the conviction was had or confirmed) whether to allow or reject the application for remission.”
- (3) The existing sub-rule (vi) of Rule 482 of Bihar Prison Manual, 2012 renumbering as sub-rule (vii) shall be substituted by the following:-
 “(vii). On receipt of the report/recommendations of the Superintendent of Police and Probation Officer and opinion of Presiding Judge of the Court (before or by which the conviction was had or confirmed), Superintendent shall put up the case to the Inspector General of Prisons and Correctional Services. The Inspector General of Prisons and Correctional Services shall examine the case, in view of the opinion of Presiding Judge of the Court (before or by which the conviction was had or confirmed) and report/recommendations of the Superintendent of Police and Probation Officer regarding the premature release of a prisoner or otherwise. While

doing so he/she shall keep in view the general or special guidelines laid down by the State Government for the State Sentence Remission Board. It shall be given proper attention to the various norms laid down and guidelines given by the Supreme Court of India and various High Courts in the matter of premature release of prisoners.”

- (4) Addition of new sub-rule (viii):- After sub-rule (vii) of rule 482 of Bihar Prison Manual, 2012, following new sub-rule (viii) shall be added namely-

“(viii) Where the life sentences is given under any central law or any other similar offence under central law, the State Government shall not have the powers to exercise remissions or commutations.”

By order of the Governor,

RAJEEV VERMA,

Joint Secretary-Cum-Director (Administration).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 431-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>